Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 9 Issue - 02 December - 2025
Total Pages - 40 Price - Rs. 25

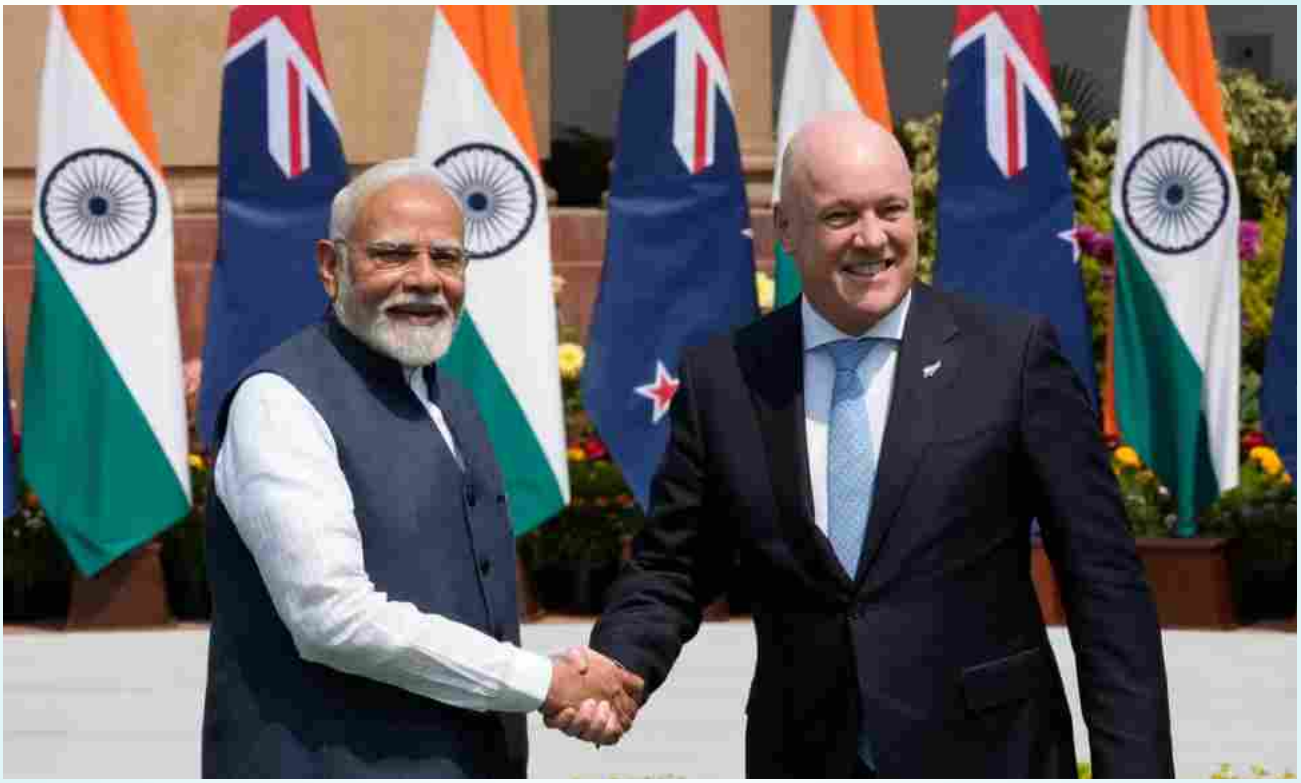

खास स्टोरी-

सामयिक - भारत-न्यूजीलैण्ड एफटीए

पड़ताल - अरावली का भविष्य

उद्यम यात्रा - नव स्तम्भ

Thar Desert, Jaisalmer

RAJASTHAN

Incredibly mesmerizing!

Department of Tourism, Government of Rajasthan

www.tourism.rajasthan.gov.in | Follow us

RAJASTHAN

The Incredible State of India !

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -9 Issue - 2 December 2025

Editorial Board

■ *Patron*

Shri Madhusudan Dadu, National President	09810256494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

■ *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

■ *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
विचारों की स्पर्धा	05
मुक्त व्यापार	07
हस्तशिल्पियों के कौशल प्रशिक्षण	11
अरावली का भविष्य	15
हौसलों की उड़ान	21
Assam Logistics	23
एलयूबी अभ्यास वर्ग	24
एलयूबी महाकौशल	26
India Stone Mart- 2026	27
New Labour Codes	29
LUB's NEWS in Brief	30

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

Renewable Energy Share Hopefully Cross 35 % by 2030

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

According to a report released recently - the share of India's electricity generation from renewable energy (RE) capacity, including large hydro projects, is expected to cross 35 percent by year 2030 from 22.1 per cent in year 2025, with expected incremental capacity addition of around 200 GW between year 25 till 30.

This, in turn, also hinges on the extent of implementation of the ongoing project pipeline where the projects are bid out and the PPAs are signed, the development of adequate transmission connectivity infrastructure as well as timely bidding for new RE projects, along with the power purchase agreements (PPAs) signing by central nodal agencies, states the report by rating agency ICRA.

The outlook for the renewable energy sector remains "stable," led by strong policy support, superior tariff competitiveness and sustainability initiatives by large commercial and industrial (C&I) customers.

However, challenges remain on the execution front, including land and transmission infrastructure, delays in signing PPAs, exposure to equipment prices and distribution utility finances.

As India grapples with variability in renewable generation, Battery Energy Storage Systems (BESS) have emerged as the important enabler for grid stability.

The Government has introduced viability gap funding for BESS capacity along with extended transmission charge waivers for storage projects until 2028, the report notes.

Further, the significant decline in battery costs over the past decade has helped reduce the cost of energy storage and adoption of BESS projects globally.

Ofcourse BESS projects have shorter lifespans and require replacement capex but sustained reduction in battery prices is expected to drive greater adoption" on the competitiveness of standalone BESS projects.

❑❑❑

इस परिवर्तनशील समय में निर्यात के लिए दोहरा बीमा

Double assurance for exports in these volatile times.

निर्यातकों के लिए ऋण जोखिम बीमा
Credit Risk Insurance for Exporters

एवं /&

बैंकों के लिए ऋण जोखिम बीमा
Credit Risk Insurance for Banks

आर्थिक अस्थिरता के इस समय में निर्यात के अनुकूल ईसीजीसी के साथ ऋण जोखिम का बीमा कराएं।

In these times of economic instability, insure against credit risk with ECGC's export-friendly credit risk covers.

अधिक जानकारी के लिए ईसीजीसी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करें।
For more information contact your nearest ECGC office.

ई सी जी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, भारत
टेली : 6659 0500 / 6659 0510 • **टोल फ्री :** 1800-22-4500
ईमेल : marketing@ecgc.in • **वेबसाइट** : www ecgc in

ECGC Limited
(A Government of India Enterprise)
Registered Office : ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M. V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069, Maharashtra, India
Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • **Toll Free :** 1800-22-4500
Email : marketing@ecgc.in • **Website** : www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918 | @ecgclimited

ADVT. NO. : NMD/198/214

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे. • You focus on exports. We cover the risks.

'विचारों की स्पर्धा हो सकती है, लेकिन सबका मन एक रहना जरूरी है'

प्रेरक पाथेय
डॉ. मोहनराव भागवत
पूज्य सरसंघचालक,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त कोलकाता में 21 दिसंबर, 2025 को आयोजित ' 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज' विषयक व्याख्यानमाला में विशेष संबोधन का संपादित अंश)

विचारों की स्पर्धा हो सकती है, लेकिन सबका मन एक रहना जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने विरोधी को रक्षा मंत्री बनाकर इसी एकता सूत्र को बढ़ाया।

संघ का काम मित्रता के आधार पर शुद्ध सात्विक कार्य है। संघ का सही से पता तब चलेगा, जब आप संघ की शाखा में प्रत्यक्ष आकर देखेंगे और समझेंगे।स्वयंसेवक सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। संघ किसी का नियंत्रण नहीं करता – न बाहर से, न अंदर से। संघ को अंदर से देखना आवश्यक है।

डॉ. हेडगेवार नहीं होते, तो संघ नहीं होता। संघ को समझने के लिए उनका चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। संघ अपनी स्थापना के दिवस से ही सामूहिकता के भाव से चलता है। संघ एक सामूहिक कार्य पद्धति है।

हिंदुस्थान हिन्दू राष्ट्र है; डॉ. हेडगेवार के समय में इसकी मान्यता नहीं थी। उस समय वे हिन्दू समाज के संगठन के लिए खड़े हुए। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में, आर्थिक रूप से बेहद अभावग्रस्त होने के बावजूद शुद्ध अंतःकरण, निस्वार्थ बुद्धि से डॉ. हेडगेवार ने संघ का कार्य प्रारंभ किया।

समाज के स्नेह के भरोसे संघ आगे बढ़ा। यह ईश्वरीय कार्य है। दुनिया के किसी स्वयंसेवी संगठन का इतना विरोध नहीं हुआ, जितना संघ का हुआ। हमले हुए और हत्याएं भी हुई, लेकिन स्वयंसेवक आगे बढ़े। एक भी स्वयंसेवक के मन में इसको लेकर कटुता का भाव नहीं है। गुरु दक्षिणा से संघ चलता है। बाहर से कुछ नहीं लेते, स्वयंसेवक सब चलाते हैं।

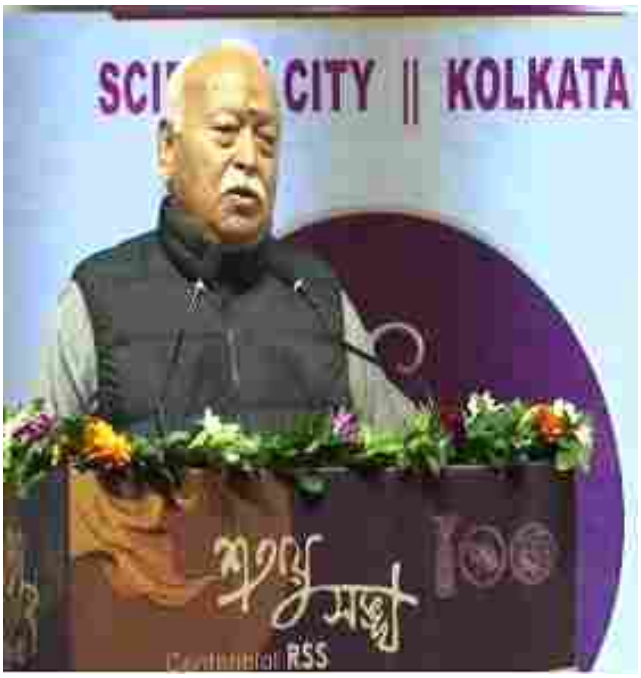

संघ आर्थिक रूप से स्वावलंबी है। पाई–पाई का हिसाब रखा जाता है और ऑडिट होता है। भारत के कुल पौने सात लाख गाँवों में से सवा लाख स्थानों में संघ है। 45,000 शहरों – नगरों में अभी हम आधे में पहुँचे हैं और आधे में पहुँचना है। विरोध के वातावरण में हम सजग रहते थे। अब अनुकूलता के वातावरण में हमें तेज गति से कार्य का विस्तार करना है। कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण हमारे शताब्दी वर्ष का एजेंडा है। समाज में बहुत बड़ी संख्या में अच्छे लोग हैं। अपने घर का पैसा लगाकर बिना प्रसिद्धि के ही समाज की सेवा में लगे लोगों की बड़ी संख्या है। हम इसे समाज की सज्जन शक्ति कहते हैं।

समाज की सज्जन शक्ति का नेटवर्क स्थापित करना, परस्पर समन्वय करना और इनमें पूरकता लाने के कार्य में संघ साथ रहेगा। देशव्यापी कार्यकर्ताओं के आधार पर सम्पूर्ण समाज में आचरण का परिवर्तन करने का समय आ गया है। आचरण अर्थात आदत में परिवर्तन करने की पांच बातों को स्वयंसेवक पहले अपने जीवन में लाएं, इसकी शुरुआत हमने संघ के शताब्दी वर्ष में की है। ये पांच विषय हैं:

सामाजिक समरसता– मंदिर, पानी, श्मशान– सब हिन्दुओं के लिए समान हो।

कुटुम्ब प्रबोधन– परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर संवाद होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन नियत समय पर परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र आना। साथ बैठकर बिना मीनमेख निकाले भोजन करना। भजन करना। और चार घंटे के समय में अपने कुटुम्ब, अपनी परंपरा की चर्चा करना।

पर्यावरण– पर्यावरण संरक्षण की चर्चा बहुत होती है, पर वह चर्चा कृति में नहीं आती। इसके लिए छोटे–छोटे उपाय हम स्वयं से करें। अपना घर स्वच्छ रहना चाहिए और सामने का रास्ता भी। पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करना, छत पर पेड़–पौधे लगाओ। लघु उद्योग भारती की ओर से राजस्थान के पाली कस्बे में संचालित स्वरोजगार का प्रकल्प कुल्हड़ उद्योग सराहनीय प्रयास है जो पर्यावरण के अनुकूल भी है और उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी कार्य हो रहा है।

स्वदेशी– स्वावलंबन और रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वयं का बोध होना चाहिए कि हम कौन हैं। अपने आचरण में स्वदेशी भाषा, भ्रमण, भेष, भोजन और भवन होना चाहिए।

संविधान– प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार हमें अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए। संविधान निर्माताओं के हिन्दू मन का भाव संविधान में प्रकट होता है।

इन पांच परिवर्तनों की पहल को लेकर हम समाज में जाने वाले हैं। हिन्दुओं की शक्ति जागरूक हो रही है और निश्चित रूप से होगी। भारत, हिन्दुस्थान और हिन्दू – ये सब समानार्थी हैं।

सबके साथ चलना, सबको साथ लेकर चलने वाला संघ के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं है। संघ सम्पूर्ण समाज को अपना मानता है। इस अपनत्व के आधार पर हम सब एक हों। सब शाखा में आएं, यह आवश्यक नहीं। आएं तो अच्छा ही है। क्योंकि संघ की शाखा के समान निस्वार्थ बुद्धि और प्रामाणिकता का प्रशिक्षण देने वाली दूसरी कोई कार्यप्रणाली (मैकेनिज्म) नहीं है। संघ श्रेय लेने के लिए काम नहीं करता है।

□□□

Important Update from Ministry of Corporate Affairs

The Ministry of Corporate Affairs has changed the rules for what counts as a Small Company in India. New limits for being a Small Company:

- Paid-up capital up to ₹10 crore, and
- Annual turnover up to ₹100 crore

If a company fits within these limits, it will be treated as a Small Company under companies act. These new rules are effective from 1st December, 2025. The Small company as per companies act now aligns with the definition of Small enterprise under MSME category as per MSMED Act, Ministry of MSME, GOI.

LUB's Chittorgarh Women Wing organized Swayamsiddha Exhibition-2025 with the theme "Rangilo Rajasthan," which was inaugurated by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra

ji. The program began with a women's self-defense demonstration presented by the Nirbhaya Sena. An inspiring performance of "Valor of Chittorgarh" was also presented by the Jai Chittorgarh-Jai Mewar Team. A special ramp walk featured women visitors, vendors, and women entrepreneurs. All the members wore Leheriya attire, conveying a message of cultural unity. The talent show deeply impressed the audience. Fifteen winners who made purchases of ₹5000 or more at the fair were also given attractive gifts. All exhibitors were honored with certificates.

On this occasion, National Secretary Smt. Anju Singh, Prant President Shri Mahesh Hurkut, General Secretary Shri Praveen Gupta, Vice President Shri Gyan Mehta, Joint Secretary Shri Praveen Tak, Swayamsiddha In-charge Smt. Reena Devi, and Bhilwara Women's Unit President Smt. Pallavi Ladha were present.

मुक्त व्यापार समझौतों में डेयरी और कृषि का बचाव

सामयिक

डॉ. अश्विनी महाजन

राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

ashwanimahajan@rediffmail.com

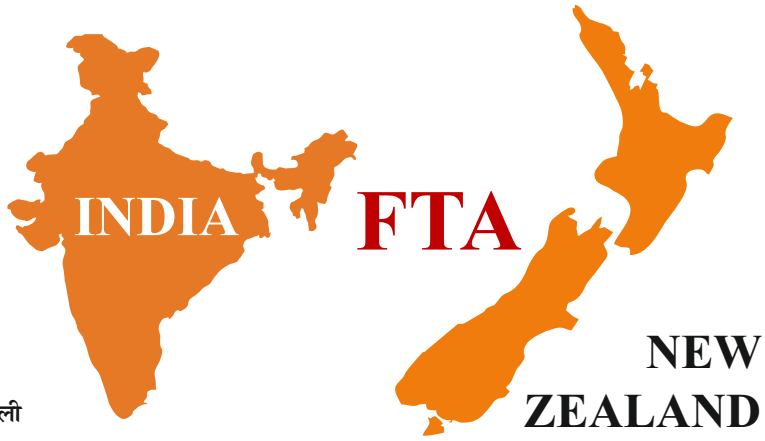

कुछ दिन पहले भारत ने न्यूज़ीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों के साथ भी एफटीए कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कुछ हैरानी से देखा जा रहा है जबकि नवंबर 2019 में भारत ने स्वयं को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) से बाहर कर लिया था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दोनों शामिल थे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ अलग–अलग एफटीए कैसे कर लिए?

आरसीईपी एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता था, जिसमें मुक्त व्यापार से जुड़े प्रावधान शामिल थे। इसमें 16 देश–10 आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत भागीदार थे। इस समझौते पर लगभग आठ वर्षों तक बातचीत चली। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत ने आरसीईपी से बाहर निकलने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि समझौते का अंतिम प्रारूप भारत की अपेक्षाओं और हितों के अनुरूप नहीं था।

4 नवंबर, 2019 को आरसीईपी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देती। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने उन्हें इस समझौते से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया।

अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अंतिम क्षण में इस समझौते से पीछे हटने का साहसिक कदम कैसे लिया? संभवतः यह विश्व इतिहास में पहली बार था जब किसी सरकार के मुखिया ने वर्षों की बातचीत और अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद भी, शिखर सम्मेलन में अन्य सभी नेताओं के सामने यह घोषणा की कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। वास्तव में, डेयरी और कृषि ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र थे, जिन पर भारत ने कठोर रुख अपनाया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मांग थी कि आरसीईपी के सदस्य देश अपने डेयरी और कृषि बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलें।

आरसीईपी से भारत के बाहर निकलने और बाद में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ अलग–अलग मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने के बीच जो विरोधाभास दिखाई देता है, उसे समझने के लिए आरसीईपी की संरचना को समझना आवश्यक है। आरसीईपी में जो 16 देश शामिल थे, इनमें से 10 आसियान देशों के साथ भारत के पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते मौजूद थे। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी भारत के एफटीए पहले से लागू थे। वहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की द्विपक्षीय एफटीए वार्ताएँ अलग–अलग चल रही थीं। इस

परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही ऐसा देश बचता था, जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए गंभीर जोखिम माना जा रहा था–और वह देश था चीन। इसलिए भारत ने आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया और इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ अलग–अलग, द्विपक्षीय समझौते करने का रास्ता चुना।

जब भारत ने अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए, तो कई लोगों को हैरानी हुई कि कृषि और डेयरी को बाहर रखते हुए यह समझौता कैसे किया गया। हालांकि, इस कदम की व्यापक सराहना भी हुई। अब जब न्यूज़ीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया गया है–और उसमें भी कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है–तो यह दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट हो जाता है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय अत्यंत सतर्क रहा है और उसने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और डेयरी, को बाहर रखने में सफलता हासिल की है।

अब प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसे देश के लिए कृषि और डेयरी की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यदि कृषि और डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल किया जाए, तो इससे भारतीय कृषि और डेयरी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उनका यह भी कहना है कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

आजीविका और खाद्य सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों से आता है, जिनके पास औसतन केवल एक या दो दुधारू पशु होते हैं। इनके लिए दूध केवल अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का आधार है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है और 8 करोड़ से अधिक परिवार यानि 36 करोड़ लोग डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं।

इसके विपरीत, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी एक व्यापार–केंद्रित उद्योग है, जहाँ उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः निर्यात और मुनाफा होता है, न कि व्यापक ग्रामीण आजीविका। निस्संदेह, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। मात्रा की दृष्टि से देखें, तो लीटर में दुग्ध उत्पादन कई प्रमुख कृषि फसलों के किलोग्राम में उत्पादन से भी अधिक है। भारत में अधिक दूध उत्पादन के पीछे प्रमुख कारण यह है कि देश में दुग्ध उत्पादों–विशेषकर दूध–के दाम अपेक्षाकृत लाभकारी हैं, जिससे छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

यह भी सर्वविदित है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुग्ध उत्पादों, विशेषकर मिल्क पाउडर, की कीमतों में भारी अंतर है। यदि न्यूज़ीलैंड का दूध या दूध पाउडर बिना शुल्क (टैरिफ) के भारत में आने लगे, तो घरेलू बाजार में कीमतों में तेज गिरावट आएगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि देश के लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे।

ऐसी स्थिति में भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बने रहने का दर्जा खो देगा, बल्कि यहाँ एक गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि दुनिया का कोई भी देश–चाहे वह कृषि उत्पाद हो या दूध–भारत जैसे विशाल देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है।

अमेरिका के साथ समझौता और कृषि

ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका–दोनों ही–एक व्यापक व्यापार समझौते पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा बनकर कृषि क्षेत्र ही उभरा है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ब्राजील के बाद, सोयाबीन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रंप टैरिफ के बाद चीन–जो

अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था–ने अमेरिका से आयात में भारी कटौती कर दी है। इसी तरह अमेरिका अन्य कृषि उत्पादों का भी अधिशेष उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए वह नए विदेशी बाज़ार तलाश रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के लिए आक्रामक रूप से प्रवेश चाहता है, जबकि भारत इसका सख़्त विरोध कर रहा है। भारत के इस विरोध के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं।

पहला, यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देता है–जो अमेरिकी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी से समर्थित हैं–तो भारतीय किसान इस असमान प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे और उत्पादन बंद करने को मजबूर हो सकते हैं। इससे आजीविका का नुकसान, बेरोजगारी में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में गिरावट आएगी, जो भारत को खाद्य असुरक्षा की ओर भी धकेल सकती है।

दूसरा, अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से भारत की जैव–सुरक्षा और बीज संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के अधिकांश कृषि उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) होते हैं और पेटेंट के अधीन होते हैं। भारत ने लंबे समय से जीएम खाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रुख अपनाया है। मज़बूत घरेलू नियंत्रणों के बिना जीएम फसलों को अपनाने से किसानों की लागत बढ़ सकती है, बीजों पर निर्भरता गहरी हो सकती है और ऐसे पारिस्थितिकी जोखिम पैदा हो सकते हैं, जिनकी भरपाई बाद में संभव नहीं होगी। इसलिए किसी भी अमेरिकी व्यापार समझौते के दबाव में जल्दबाजी करने के बजाय, भारत के लिए वैज्ञानिक विवेक और स्वदेशी अनुसंधान को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

यदि अमेरिका भारत के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हुए एफटीए से संकेत ले और अपनी मांगों को यथार्थवादी स्तर तक सीमित करे, तो भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में आ रही बाधाओं का समाधान निकालना कठिन नहीं होगा।

भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के निहितार्थ

हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के भारत के लिए सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण–दोनों प्रकार के निहितार्थ हैं, इसलिए इसे संतुलित और सतर्क दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात पर आधारित है, विशेषकर डेयरी, मांस और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में। ये क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं, क्योंकि करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों तथा सहकारी आधारित डेयरी व्यवस्था की आजीविका इन्हीं से जुड़ी हुई है। इन क्षेत्रों में व्यापक टैरिफ रियायतें भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती हैं।हालांकि इस समझौते में मोटे तौर पर डेयरी को बाहर रखा गया है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के प्रसंस्करण को खोला गया है। इस संबंध में विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा ताकि भारतीय डेयरी का अहित न होने पाए।

दूसरी ओर, यह एफटीए भारत के लिए कुछ अवसर भी प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशेवर सेवाओं तथा कुशल मानव संसाधन की आवाजाही में सुधार की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दवाइयों, वस्त्रों, इंजीनियरिंग उत्पादों और कुछ विनिर्मित वस्तुओं के लिए न्यूज़ीलैंड के बाजार में बेहतर पहुँच मिल सकती है, हालांकि न्यूजीलैंड का बाजार आकार में छोटा होने के कारण कुल लाभ सीमित रह सकते हैं।

रणनीतिक दृष्टि से भी इस समझौते के महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, डेटा प्रवाह और सरकारी खरीद से जुड़े प्रावधान भारत की नीतिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने की भारत की क्षमता को कमजोर न करे। साथ ही, न्यूज़ीलैंड के माध्यम से अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादों के अप्रत्यक्ष प्रवेश की संभावना पर भी सतर्कता जरूरी है।

कुल मिलाकर, भारत–न्यूज़ीलैंड एफटीए से सेवाओं और कुछ उच्च मूल्य वाले निर्यात क्षेत्रों में अवसर अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन कृषि और एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं। यह समझौता भारत के संतुलित व्यापार, घरेलू क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

नव उत्थान - नई पहचान
बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

गर्भवती महिलाओं में एनीमिया नियंत्रण हेतु विशेष अभियान

पिंक पखवाड़ा

FCM

फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज

गर्भावस्था में एनीमिया दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका

- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाने में सहायक।
- मात्र एक डोज़ से 45 दिनों के भीतर हीमोग्लोबिन में 2-6 ग्राम तक की वृद्धि।
- दूसरी और तीसरी तिमाही में Hb <10 g/dL वाली गर्भवती महिलाएं।
- अब राजस्थान में PHC स्तर तक उपलब्ध।
- प्रति वर्ष लगभग 4 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभ।
- निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में FCM का IV इन्फ्यूजन लगवाएं।

गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद।
अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का केवल एक IV इन्फ्यूजन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं!

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें टोल फ्री : 104/108

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

हस्तशिल्पियों के कौशल प्रशिक्षण से रोजगार सृजन के साथ हो रहा सशक्तिकरण
राष्ट्रप्रथम एवं लोकसेवा की भावना से लघु उद्योग भारती सक्रिय

उत्सव
मंजू सारस्वत
प्रदेश संयुक्त महासचिव
लघु उद्योग भारती, राजस्थान
harekrishnaindustries@gmail.com

राजस्थान के मारवाड़ के गौरव के रूप में स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र जोधपुर में एक बार फिर हस्तशिल्पियों की रौनक देखने को मिली। अवसर था 35 वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2026 के आयोजन का, जिसका औपचारिक उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 26 दिसंबर, 2025 को किया।

प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री श्री केके विश्नोई, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक, डेयरी–पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री नरेश पारीक, सांसद श्री राजेन्द्र गहलोत, विधायकगण श्री देवेन्द्र जोशी, श्री अतुल भंसाली व श्री अर्जुनलाल गर्ग, अमृता देवी राज्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह विश्नोई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक श्री हरदयाल वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के उत्साह को बड़ा कर दिया।

जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले में लघु उद्योग भारती नोडल एजेंसी है।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण सर्वोपरि है और इसी को केंद्र में रखकर सरकार नई नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि संकल्प–पत्र में किये गए 70 प्रतिशत वादों को सरकार ने पूरा कर दिया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग संगठन भारती राष्ट्रप्रथम की विचारधारा एवं लोकसेवा की भावना के साथ कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव से पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग का वैश्विक केन्द्र बन सकेगा।

हस्तशिल्पियों ने परंपरा का किया संरक्षण–

मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है तथा इन्होंने परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। यह श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम भी बना है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों को कौशल प्रशिक्षण देते हुए नए मार्केट लिंकेज दिए जा रहें हैं जिससे वे अपने उत्पादों को उचित दाम पर बेच सकें। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1,197 दस्तकारों को परिचय–पत्र जारी किए हैं। राज्य सरकार की बुनकर पुरस्कार योजना, बाजार सहायता योजना एवं चर्म प्रशिक्षण योजना से हस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचा है। माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें भी दी गई हैं।

आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार–

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। राजीविका के माध्यम से प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण पाकर 12 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी हैं।

इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना में 21 लाख 73 हजार व्यक्तियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। योजना के तहत 54 हजार 202 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 ट्रेड्स के दस्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था को गति देने 28 नीतियां जारी–

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 4 लाख तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन के लक्ष्य में अब तक 92 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं 1 लाख 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही, निजी क्षेत्र में 2.50 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने 28 नवीन नीतियां जारी की।

एमएसएमई क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्य–

श्री शर्मा ने कहा कि राज उद्योग मित्र पोर्टल पर 3,266 एमएसएमई उद्यमों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति–2024 को 8 दिसम्बर, 2024 को अधिसूचित किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के 7 हजार 186 आवेदकों को 1946.84 करोड़ रुपये ऋण वितरण और 436.82 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया गया। उन्होंने कहा कि रीको द्वारा 31 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 2,862 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। जोधपुर के बोरानाड़ा विस्तार क्षेत्र में 161.75 एकड़ पर हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क विकसित किया गया तथा चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दो प्रमुख सिरेमिक जोन विकसित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में बन रहा उद्योग हितैषी वातावरण–

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिप्स को अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित कर स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण से संबंधित पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए गए। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा 332 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्यात को 1.50 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के दो साल के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित किया गया। कार्यक्रम में श्री हरीश लोहिया द्वारा सम्पादित उत्सव स्मारिका का विमोचन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंच गौरव प्रदर्शनी का अवलोकन कर दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की तथा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन–

हस्तशिल्प उत्सव में आयोजित प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन को उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने महिला नेतृत्व, स्वावलंबन और औद्योगिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में महिला नेतृत्व निर्णायक है। राजस्थान

केवल भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि विचार, संस्कृति और उद्यमशीलता की परंपरा है, जहाँ हर जिले गांव का कोई न कोई उत्पाद महिलाओं के परिश्रम और सपनों से जुड़ा है। उन्होंने महिलाओं को सरल ऋण सुविधा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना और उनके उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजु बजाज एवं श्रीमती अंजू सिंह, जिला उद्योग केन्द्र की संयुक्त निदेशक श्रीमती पूजा मेहरा सुराणा, श्रीमती रूमादेवी तथा एसीपी श्रीमती छवि शर्मा उपस्थित रहीं।

आर्थिक समृद्धि एवं उत्थान में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी की भूमिका विषय पर संगोष्ठी में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक एवं डेयरी, पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत, सहकार भारती प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र थानवी, सहकार भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक बाहेती, सहकार भारती प्रदेश

उपाध्यक्ष श्री महेंद्र दवे ने सक्रिय सहभागिता की।

मोहक झांकियां और सांस्कृतिक आयोजन बने आकर्षण के केंद्र- सेंट्रल पंडाल में सियाचिन ग्लेशियर बॉर्डर पर सेना के शीर्य को प्रदर्शित करने वाली झांकी, बोइंग विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, एस 400 की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र रहे। उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में भी

लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

समापन समारोह-

हस्तशिल्प उत्सव का समापन समारोह 4 जनवरी को सैनाचार्य श्री अचलानंद महाराज, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम ओझा, धर्मजागरण क्षेत्रीय प्रमुख श्री ललित शर्मा, डीआईजी जेल श्री राकेश मोहन, जोधपुर की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया।

मेला समन्वयक श्री महावीर चोपड़ा ने हस्तशिल्प उत्सव को सफल आयोजन बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने आर्टिजन और छोटे उद्यमियों को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया साथ ही जोधपुर को लघु उद्योगों का हब बनाने योगदान दिया।

एलयूबी जोधपुर प्रान्त अध्यक्ष श्री बालकिशन परिहार ने बताया कि नोडल एजेंसी के तौर पर लघु उद्योग भारती की टीम ने इस आयोजन को स्थापित कर दिया है, जिस वजह से राज्य सरकार ने संगठन को 2029 तक के आयोजन की जिम्मेदारी दी है। हस्तशिल्प उत्सव पश्चिम राजस्थान की ब्रांडिंग में एक महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध हुआ है।

जोधपुर प्रांत महामंत्री श्री सुरेश कुमार विश्नोई ने बताया कि 11 दिवसीय मेले में जोधपुर शहर के साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की एवं आर्टिजन और छोटे उद्यमियों के उत्पादों को सराहा और खरीदी की।

आयोजन सचिव श्री एस. एस. पालीवाल और अतिरिक्त आयुक्त पूजा मेहरा ने अतिथियों, मेला आयोजन नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती की टीम का आभार जताते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव सभी के संयुक्त प्रयासों से ही सफल हुआ है।

□□□

लघु उद्योग भारती

LAGHU UDYOG BHARTI

JALANDHAR

VIVEK RATHOUR
PAST PRESIDENT

ANIRUDH DHIR
PRESIDENT

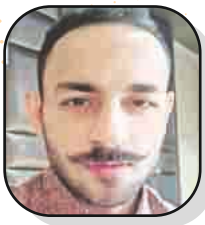

VARUN BHALLA
GRN. SECT

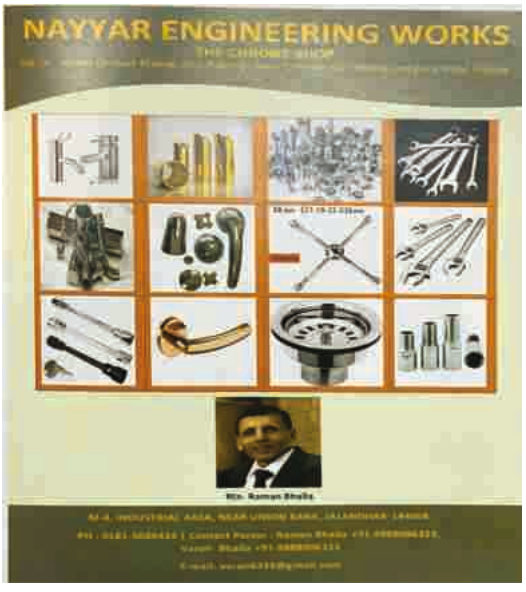

अरावली का भविष्य: भावनात्मक प्रतिबंध या वैज्ञानिक प्रबंधन ?

(सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, वैश्विक आर्थिक मॉडल और भारत के विकास का संतुलन)

पड़ताल

मधुसूदन पालीवाल

सीनियर कंसल्टेंट एवं

रिटायर्ड सुपरिनटेंडिंग माइनिंग इंजीनियर,

डीएमजी, राजस्थान

paliwalms@gmail.com

अरावली पर शीर्ष अदालत के निर्णय को कुछ राजनीतिक दलों और अन्य संस्थानों ने इस तरह प्रस्तुत किया कि जैसे अरावली अब खतरे की जद में आ गई। अब जबकि भ्रम की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है, इसके बावजूद आज भी हम एक दोराहे पर जरूर खड़े हैं। एक ओर जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी (Ecology) को बचाने की वैश्विक जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। क्या हम पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी खनिज संपदा को हमेशा के लिए ताले में बंद कर सकते हैं? या क्या कोई ऐसा 'मध्यम मार्ग' है जो प्रकृति और प्रगति दोनों को साथ लेकर चले? यह लेख इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है।

1. केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल

भारत सरकार ने हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, अब अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन लीज (Mining Lease) की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, पूरे अरावली परिदृश्य को एक विस्तारित 'संरक्षित क्षेत्र' (Protected Zone) के रूप में परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सतही तौर पर देखने पर यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम प्रतीत होता है। जनता की बढ़ती चिंताओं और सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों के बीच यह फैसला राहत देने वाला लग सकता है। लेकिन, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, हमें भावनाओं के ज्वार से बाहर निकलकर तथ्यों की ठोस जमीन पर खड़े होकर सोचना होगा।

राज RAS और अन्य भूगोल स्रोतों के अनुसार, अरावली राजस्थान में उत्तर–पूर्व में खेतड़ी (झुंझुनू/सीकर क्षेत्र) से लेकर दक्षिण–पश्चिम में खेड़ब्रह्मा/माउंट आबू क्षेत्र तक की लंबाई में विस्तृत है। पूरी अरावली श्रृंखला की कुल 37 जिलों में उपस्थिति मानी जाती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं।

अरावली विवाद की कानूनी यात्रा

अरावली विवाद का इतिहास केवल खनन से नहीं, बल्कि हरियाणा के सोहना–रेज़ीना क्षेत्र में कॉलोनी और फार्म हाउस जैसे अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ 1980 के दशक के अंत और 1989 के आसपास दायर जनहित याचिकाओं से शुरू होता है। इन PILs के आधार पर केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 7 मई, 1992 का ऐतिहासिक 'अरावली नोटिफिकेशन' जारी किया, जिसके द्वारा हरियाणा के गुड़गांव और राजस्थान के अलवर जिले में पाँच राजस्व श्रेणियों – 'गैर–मुमकिन पहाड़', 'गैर–मुमकिन राड़ा', 'गैर–मुमकिन बे–हेड', 'बंजर बीड' और 'रौंड़'– को विशेष अरावली क्षेत्र मानते हुए उन पर नई खनन, औद्योगिक निर्माण और बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध

लगा दिया गया। 2002 तक इस ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा के कोटे और अलमपुर गांव में अवैध खनन के कारण मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में उठा; पहले दिल्ली–हरियाणा सीमा से 5 किमी क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित किया गया, पर हरियाणा राज्य की लगातार अवज्ञा और अवैध खनन स्थलों व पुनर्वास की अनदेखी के चलते 29/30 अक्टूबर, 2002 को पूरे अरावली क्षेत्र पर पूर्ण खनन प्रतिबंध लगा दिया गया। स्थानीय स्तर की यह समस्या हरियाणा राज्य की गैर–अनुपालना के कारण धीरे–धीरे राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बनी, और आज प्रस्तावित Management Plan for Sustainable Mining (MPSM) उसी ऐतिहासिक सबक से प्रेरित एक प्रयास है कि बिना नियोजन के पूर्ण प्रतिबंध के बजाय कड़ा, वैज्ञानिक और पारदर्शी नियमन अधिक प्रभावी होता है।

2. 'अंधाधुंध खनन' का मिथक और जमीनी हकीकत

अरावली के बारे में सबसे प्रचलित धारणा (Narrative) यह है कि "पूरी पर्वत श्रृंखला को खनन माफिया द्वारा खोदा जा रहा है" और "पहाड़ गायब हो रहे हैं"। यह एक भावनात्मक सच हो सकता है, लेकिन यह सांख्यिकीय और वैज्ञानिक सत्य नहीं है।

आंकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर एक अलग तस्वीर उभरती है। कानूनी रूप से अनुमत खनन एवं खनिज संभावित क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल के मात्र 2% से भी कम हिस्से पर होता है। शेष 98% भूमि में जिसमें घने वन क्षेत्र, कृषि भूमि, चारागाह, अभयारण्य और पारंपरिक आदिवासी भूमि शामिल हैं। ये विशाल क्षेत्र पहले से ही वन संरक्षण अधिनियम (1980) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), पर्यावरण नियमों आदि के तहत पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ खनन की अनुमति कभी थी ही नहीं।

अतः, यह तर्क देना कि यह सीमित क्षेत्र में खनन पूरी अरावली पारिस्थितिकी को नष्ट कर रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। समस्या खनन का होना नहीं है, बल्कि समस्या यह सुनिश्चित करना है कि यह खनन अपने निर्धारित माप दंडों के तहत 2% क्षेत्र से बाहर न फैले।

3. आर्थिक अनिवार्यता: जीडीपी और वैश्विक महाशक्तियां

पर्यावरण भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन पेट भरने के लिए अर्थव्यवस्था की मजबूती भी अनिवार्य है। किसी भी देश का विकास उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) – सड़कें, पुल, भवन, हवाई अड्डे–पर निर्भर करता है, और इन सबके लिए 'खनिज' रीढ़ की हड्डी हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ (IMF) के नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण यह साबित करता है कि पर्यावरण और खनन एक–दूसरे के दुश्मन नहीं हैं।

तालिका:
शीर्ष 10 देशों की जीडीपी में खनन के योगदान की स्थिति

GDP में खनन का सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 10 देश

क्र. स.	रैंक	देश	GDP में खनन का योगदान	प्रमुख खनिज / टिप्पणी
1	1	ऑस्ट्रेलिया	10–12%	लौह अयस्क, लिथियम, कोयला; विश्व की अग्रणी खनन अर्थव्यवस्था
2	2	रूस	>10%	पैलेडियम, सोना, निकेल
3	3	पेरू	>10%	तांबा, चांदी, जस्ता
4	4	चीन	7–9%	रेयर अर्थ तत्व, कोयला; उच्चतम कुल उत्पादन
5	5	दक्षिण अफ्रीका	7–9%	प्लेटिनम, सोना, हीरा
6	6	ब्राज़ील	5–6%	लौह अयस्क, निकेल, सोना
7	7	कनाडा	4–5%	सोना, निकेल, यूरेनियम
8	8	इंडोनेशिया	3–4%	निकेल, कोयला, तांबा
9	9	अर्जेंटीना	~3%	लिथियम, तांबा (तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र)
10	10	भारत	2–3%	कोयला, लौह अयस्क; विविधीकृत अर्थव्यवस्था

इस तालिका से एक स्पष्ट रुझान सामने आता है कि दुनिया के शीर्ष 10 देशों की जीडीपी में खनन के योगदान वाले देशों ने खनन बंद करके तरक्की नहीं की, बल्कि उन्होंने खनन को 'प्रबंधित' (Managed) करके तरक्की की है। यदि भारत इन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में अपनी जगह पक्की करना चाहता है, तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को ताले में बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकते।

भारत, जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीर्ष 3 में आने का लक्ष्य रखता है, अपने खनिज संसाधनों को ताले में बंद करके यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। खनन भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है और लाखों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। हमें निर्माण सामग्री (रोड़ी, बजरी, पत्थर) और औद्योगिक खनिज इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। हम इससे अपनी मुद्रा (Forex) खर्च को बचाते हैं अन्यथा वही खनिज हमें खरीदने पड़ेंगे, जो हमारे पैरों के नीचे मौजूद हैं। यह न तो 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुकूल होगा और न ही आर्थिक रूप से इसे समझदारी कहा जाएगा।

4. परिभाषाओं का द्वंद्वः सुप्रीम कोर्ट और तकनीकी स्पष्टता

अरावली विवाद की जड़ में भूगर्भीय (Geological) और कानूनी (Legal) परिभाषाओं की अस्पष्टता रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया हस्तक्षेप ने इस धुंध को साफ करने का प्रयास किया है। हमें इन तकनीकी परिभाषाओं को समझना होगाः

(क) अरावली हिल्स (Aravali Hills):

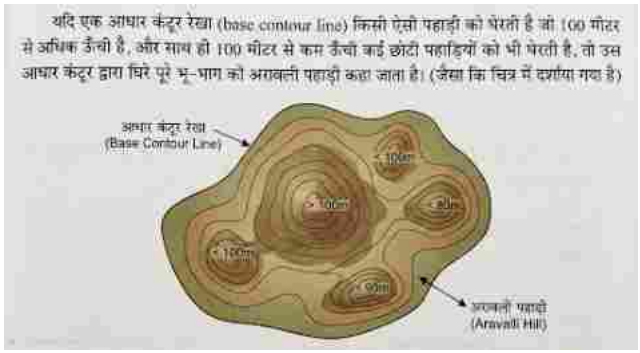

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अरावली माने गए जिलों में स्थित कोई भी भू–आकृति, जो स्थानीय सतह से 100 मीटर या अधिक ऊँची हो, उसे 'अरावली पहाड़ी' माना जाएगा। इस पहाड़ी के चारों ओर जो सबसे निचला कंटूर (Contour) उसे घेरता है, उसके भीतर आने वाला पूरा क्षेत्र–चोटी, ढलान, तलहटी (Foothills) और उससे जुड़ी छोटी–मोटी आकृतियाँ–सभी 'अरावली हिल' का हिस्सा मानी जाएँगी। इस क्षेत्र में खनन के पट्टे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

(ख) अरावली रेंज (Aravali Range):

यदि दो या अधिक ऐसी पहाड़ियाँ (जो 100 मीटर की शर्त पूरी करती हैं), एक–दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों, तो उनके बीच की घाटियाँ, निचले टीले और 'Intervening Slopes' भी पूरे "रेंज" का हिस्सा माने जाएँगे। इसलिए यह कहना गलत है कि "100 मीटर से कम ऊँचाई वाले सभी क्षेत्र खनन के लिए खुले हैं"। यदि कोई नीची पहाड़ी इस 500 मीटर की 'रेंज' में आती है, तो वह स्वतः ही संरक्षित हो जाती है।

(ग) राज्यों की विसंगतियां और सुप्रीम कोर्ट का सुधार:

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अब तक हर राज्य अपनी सुविधा से अरावली को परिभाषित कर रहा थाः

1. राजस्थान ने 2002 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर "रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण" (Richard Murphy Classification) को अपनाया था। राज्य ने 'अरावली पहाड़ी' की परिभाषा के लिए स्थानीय सतह से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के मानदंड का उपयोग किया व अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी गई।

2. हरियाणा मुख्य रूप से 7 मई, 1992 की MoEF अधिसूचना पर निर्भर था, जिसने केवल गुड़गांव और नूंह जैसे जिलों में खनन को प्रतिबंधित किया था। राज्य ने संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900 का उपयोग किया और अक्सर यह तर्क दिया कि जो पहाड़ PLP। सूची में नहीं हैं या जहाँ वन नहीं हैं, वे विकास (Real Estate) के लिए खुले हैं।

3. दिल्ली में अरावली को 'दिल्ली रिज' (Delhi Ridge) के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ परिभाषा ब्रिटिश कालीन

अधिसूचनाओं और 1996 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित थी। इसका मुख्य मानदंड ऊंचाई के बजाय विशिष्ट 'रिज क्षेत्र' और उसकी भू–आकृति (Morphological features) की रक्षा करना था।

4. गुजरात के पास अरावली के लिए कोई विशिष्ट

1. **लैंडस्केप स्तर की योजना:** खनन को टुकड़ों में देखने के बजाय पूरे अरावली इकोसिस्टम के संदर्भ में देखा जाए।
2. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** अवैध खनन को रोकने के लिए मानवीय गश्त के बजाय ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और AI–आधारित निगरानी का उपयोग हो।

'नो–माइनिंग' परिभाषा नहीं थी। राज्य ने अरावली रेंज (साबरकांठा, बनासकांठा आदि जिलों में) को केवल सामान्य वन भूमि या राजस्व भूमि के रूप में माना, और इसे पर्वत श्रृंखला के रूप में कोई विशेष सुरक्षा दर्जा नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आदेश इन अलग–अलग परिभाषाओं को खत्म कर एक एकीकृत वैज्ञानिक परिभाषा (Unified Scientific Definition) लागू करता है, जो स्वागत योग्य है।

5. 'सतत खनन प्रबंधन योजना' (MPSM) – असली समाधान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे सकारात्मक पहलू 'सतत खनन प्रबंधन योजना' (Management Plan for Sustainable Mining & MPSM) का प्रस्ताव है। कोर्ट का इरादा खनन को हमेशा के लिए बंद करना नहीं, बल्कि उसे एक 'वैज्ञानिक ढांचे' में लाना है। सरकार द्वारा "नई लीज पर रोक" लगाना केवल एक अस्थायी विराम (Temporary Pause) होना चाहिए, जब तक कि यह MPSM तैयार नहीं हो जाता। एक प्रभावी MPSM के तीन स्तंभ होने चाहिए:

3. **पुनर्ग्रहण (Reclamation)**: 'माइन क्लोजर' (Mine Closure) के बाद जमीन को वापस हरा–भरा करने की कानूनी बाध्यता हो, जैसा कि अमेरिका और कनाडा में होता है।

6. प्रतिबंध का विरोधाभास (The Paradox of Bans)

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अनुभव बार–बार यह साबित करते हैं कि "पूर्ण प्रतिबंध" (Blanket Bans) अक्सर उस उद्देश्य को ही विफल कर देते हैं जिसके लिए वे लगाए जाते हैं।

जब सरकार कानूनी, कर–भुगतान करने वाले और नियमों का पालन करने वाले खनिकों को रोक देती है, तो बाजार में मांग (Demand) खत्म नहीं होती। निर्माण कार्य नहीं रुकते, सड़कों का बनना बंद नहीं होता।

परिणामस्वरुप इस मांग को पूरा करने के लिए 'खनन माफिया' और आपराधिक सिंडिकेट (Syndicates) का उदय होता है। ये अवैध खनिक न तो रॉयल्टी देते हैं, न पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं, और न ही वैज्ञानिक तरीके से

खनन करते हैं। वे रात के अंधेरे में पहाड़ों को खोखला करते हैं। इसलिए, एक "पारदर्शी, अच्छी तरह से मैप की गई और कड़ाई से लागू नियामक व्यवस्था" (Transparent Regulatory Regime), एक अंधी रोक (Blind Ban) की तुलना में पारिस्थितिकी, भूजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में कहीं अधिक प्रभावी है।

7. अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का 'रिव्यू मोड' – नई परिभाषा रोकी, उच्च स्तरीय समिति से दोबारा जाँच, पुराना संरक्षण ढांचा बहाल

"ताज़ा संशोधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि समिति की रिपोर्ट और 20.11.2025 के फैसले के खिलाफ बहुत–सी IA/MA और याचिकाएँ आईं; वैज्ञानिक आधार पर उन्हें तुरंत स्वीकारने की वजह तो नहीं दिखी, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि परिभाषा और निर्देशों में कुछ "महत्त्वपूर्ण अस्पष्टताएँ" रह गई हैं, जिनके कारण गलत व्याख्या और गलत निर्देश लागू होने का खतरा है। इसी आशंका और व्यापक जन–आलोचना को देखते हुए कोर्ट ने 20.11.2025 के आदेश की सिफारिशों और नई परिभाषा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति से पूरे मॉडल की पुनः समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, अरावली की कानूनी परिभाषा 2010 की FSI रिपोर्ट के अनुसार रहेगी और अरावली क्षेत्र में नई या नवीनीकृत खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा, जब तक कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति न मिल जाए।"

निष्कर्ष: आगे की राह

अरावली का मुद्दा केवल 'पर्यावरण बनाम विकास' का नहीं, बल्कि 'खराब प्रबंधन बनाम वैज्ञानिक प्रबंधन' का है। सरकार की "नो न्यू लीज" (No New Lease) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली क्षेत्र में नई अथवा नवीनीकृत खनन लीज़ पर लगाई गई रोक को एक अस्थायी विराम (Pause) के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पूर्ण विराम (Full Stop) के रूप में। आगे की राह तीन स्तरों पर साफ दिखाई देती है:

1. वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और MPSM

सर्वोच्च न्यायालय ने नई ऊँचाई–आधारित परिभाषा और 20.11. 2025 की सिफारिशों को फिलहाल स्थगित कर, एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति से पूरे मॉडल की वैज्ञानिक समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ, Management Plan for Sustainable Mining (MPSM) को इस तरह अंतिम रूप देना ज़रूरी है कि अरावली की पूरी पारिस्थितिक इकाई–ऊँची पहाड़ियाँ, निचले रेंज, कॉरिडोर और recharge क्षेत्र–एक साथ सुरक्षित रहें, और जहाँ भी खनन हो, वह सख्त शर्तों और स्पष्ट सीमाओं के भीतर हो।

2. तकनीक-आधारित सीमा और निगरानी

ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और GIS–मैपिंग के जरिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सक्रिय खनन क्षेत्र राज्य की कुल भूमि के लगभग 2% से अधिक न फैले और 100 मीटर से ऊँचे तथा जल–संचय व जैव–विविधता दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ों, ढालों और गलियारों को पूरी तरह नो–माइनिंग जोन के रूप में संरक्षित रखा जाए।

अवैध खनन और ओवर–एक्सट्रैक्शन पर वास्तविक समय (real-time) निगरानी तथा कठोर दंड व्यवस्था ही सतत खनन की विश्वसनीयता बनाए रख सकती है।

3. वैश्विक सीख और भारतीय सन्दर्भ का संतुलन

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में खनन जीडीपी का 4-15% तक योगदान देता है, फिर भी वहाँ कठोर पर्यावरणीय कानूनों (Impact Assessment, जल और habitat संरक्षण, अनिवार्य reclamation bond) के तहत नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाती राजस्थान/भारत में खनन का हिस्सा अभी लगभग 2% के आसपास है, फिर भी हम US-Canada मॉडल की तरह ही MPSM, पर्यावरणीय मंजूरियाँ, वन स्वीकृति और क्लोजर–प्लान को सख्ती से लागू करके अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संतुलित रास्ता चुन सकते हैं।

अंततः, हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक विकसित भारत के लिए खनिजों की आवश्यकता है और एक रहने योग्य भारत के लिए अरावली की। समझदारी इन दोनों को एक–दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रबंधन, पारदर्शी शासन और सामूहिक ज़िम्मेदारी के माध्यम से संतुलन बनाने में है।

❑❑❑

राष्ट्रोद्धारो लघूद्यमैः

लघु उद्योग भारती

LAGHU UDYOG BHARTI

PHAGWARA

INDER PAUL KHURANA
President

ARVIND BAGGA
Hony. Secretary

ANUJ JAIN
Treasurer

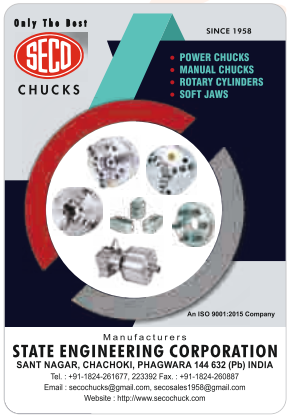

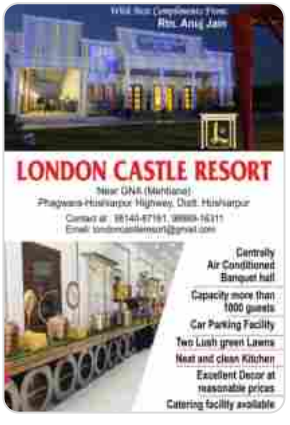

हौसलों की उड़ान और दृढ़ संकल्प से अर्जित की सफलता

उद्यम यात्रा
कपिल सुराणा
मेंबर, गवर्निंग बोर्ड- CDOS
संयोजक, स्टोनमार्ट-2026 चित्तौड़ प्रांत,
लघु उद्योग भारती, उदयपुर
Ksurana@warmestein.com

(लघु उद्योग भारती से जुड़े सदस्यों की उद्यम यात्रा में प्रस्तुत है राजस्थान के प्रेरक उद्यमी की कहानी)

उदयपुर (मेवाड़) की पवित्र भूमि पर जन्मे कपिल ने मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम इंजीनियर के रूप में Patni Computers से अपने करियर की शुरुआत की। अपनी कड़ी मेहनत, निष्ठा और अनुशासन के बल पर उन्हें जल्दी ही अमेरिका में ऑन–साइट अवसर मिला। वहाँ Gillette, Sara Lee, Coca Cola, Pitney Bowes जैसे प्रतिष्ठित क्लाइंट्स के लिए SAP कंसल्टेंट के रूप में काम किया और केवल एक वर्ष में ही उन्होंने Deloitte Consulting US के सबसे युवा Senior Consultant बनने का गौरव हासिल किया–जहां मल्टी मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने Aptive Solutions LLC नाम से अपनी कंपनी शुरू की और भारत व अमेरिका–दोनों देशों में 50 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। जीवन उन्नति के शिखर पर था..... तभी एक दिन घर से उनके दादा जी का पत्र आया– लिखा था– "घर लौट आओ बेटे, हमें तुम्हारी ज़रूरत पैसे से ज्यादा है।" इन शब्दों ने कपिल के दिल को झकझोर दिया, और उनके मन में देश के प्रति जागे कर्तव्य बोध ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। वे उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया अंतिम चरण में होने के बावजूद भी उसे रद्द कर दिया क्योंकि उनके लिए मातृभूमि सर्वोपरि थी।

भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने पारिवारिक पत्थर उद्योग को सँभालने का निर्णय लिया–जो उस समय कठिन दौर से गुजर रहा था। एक संगठित और तकनीकी क्षेत्र से पूर्णतः असंगठित उद्योग में प्रवेश करना आसान नहीं था, परंतु कपिल ने चुनौतियों को अवसर बनाया।

अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का प्रयोग कर उन्होंने फैक्ट्री में प्रक्रियाओं को सरल, आधुनिक और कुशल बनाया। जल्द ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी पहचान Precision Stone Working के लिए बनने लगी। और देखते ही देखते–एक फैक्ट्री से बढ़कर दो साल में तीन फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गईं।

2014 में उन्होंने भारत की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत पत्थर प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना का निर्णय लिया। कपिल बताते हैं कि उदयपुर में सस्ती औद्योगिक भूमि की कमी से नई फैक्ट्री की स्थापना में अत्यधिक संघर्षों से गुजरना पड़ा।

सबसे पहले सरकारी विभागों में ज़मीन आवंटन के लिए 2–3 वर्षों तक लगातार प्रयास किए, पर कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। अंततः स्वयं कृषि भूमि खरीदकर उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में भी लगभग दो वर्ष लग गए। आख़िरकार, उदयपुर के निकट एक विश्वस्तरीय इंफ्रा–स्ट्रक्चर वाली अत्याधुनिक फैक्ट्री स्थापित की गई।

आज उनका उद्योग–Nakoda Marble Industries-विश्वभर में उच्च गुणवत्ता और सूक्ष्म तकनीकी कार्य के लिए जाना जाता है। इनके पत्थर उत्पाद 30 से ज़्यादा देशों में निर्यात किये जाते है। इनके पास स्वयं की दो माइन्स डूंगरपुर और बाबरमाल में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त चार अन्य माइन्स का पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट भी पास है। फैक्ट्री में प्रयुक्त अधिकतर कच्चा माल इन्हीं अपनी माइन्स से प्राप्त होता है।

उद्योग के वित्तपोषण में भी राजस्थान के चुनिंदा उद्यमियों में कपिल शामिल थे जिन्होंने विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) में ऋण लिया। हालांकि इसे प्राप्त करने और बैंक को समझाने में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

एक सफल उद्यमी होने के साथ श्री कपिल ने राजस्थान के

पत्थर उद्योग के विकास, सुधार और नीतिगत परिवर्तन के लिए भी लगातार आवाज उठाई। उन्होंने मार्बल पर GST, मार्बल आयात नीति और अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को शीर्ष अधिकारियों व सरकार तक मजबूती से उठाया–और कई मामलों में सफलता भी हासिल की।

खेल और फिटनेस के प्रति समर्पण

कपिल NMI Skate Arena के संस्थापक भी हैं–जो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पीड स्केटिंग ट्रैक है। वे बच्चों और युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और

खेल संस्कृति विकसित करने के लिए कई खेल गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है– "स्वस्थ नागरिक ही एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं" कपिल की ये कहानी हरेक उस युवा की कहानी है जिसने अपने सपनों को देशभक्ति से जोड़ा, विदेश की चमक को ठुकराकर मातृभूमि की मिट्टी को चुना। और एक उद्योग को नई दिशा देकर यह साबित किया कि सच्ची सफलता वही है जो राष्ट्र को भी आगे बढ़ाए।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

❑❑❑

LUB & CII signed A Significant MoU

Under the able guidance of LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, an MoU was signed between LUB & CII on the first anniversary of Sohan Singh Memorial Skill Development Centre at Jaipur on 12th Dec. Shri S.R. Chaudhary, Executive Director CII, and Shri Naresh Pareek, National Jt. GS, Smt. Anju Singh, National Secretary, and Shri Mahendra Khurana, State VP from Laghu Udyog Bharti, signed the MOU.

On this occasion, the LUB Startup Conclave was organised. The main speakers were Shri Nishant Patni, Shri Gaurav Chaudhary, Smt. Anila Sancheti Chordia, Shri Girish Gupta, and Dr. Rohit Jain. In addition, LUB and CII jointly organized a job fair, in which 427 candidates registered. State GS Shri Sudhir Garg, Vice President Shri Natwarlal Ajmera & Treasurer Shri Arun Jajodia, Anchal GS Ms. Sunita Sharma and Smt. Vaishali Vashishth were also present.

Assam Logistics & Warehousing Policy

Assam, as the gateway to Northeast India and the ASEAN region, is rapidly transforming into a strategic logistics hub.

North-East Special

Udyog Times Desk

The Assam Logistics & Warehousing Policy aims to integrate transport networks, enhance multi-modal connectivity, and make the state a preferred destination for supply chain investments.

Key New Initiatives & Reforms:

Multi-Modal Logistics Infra

Development of integrated logistics parks at critical nodes such as Jogighopa, Silchar, and Baihata Chariali. Jogighopa coming up as a Multi-Modal Logistics Park (MMLP) under Bharatmala & Sagarmala with road, rail, and inland waterways convergence. Proposed MMLP will support container handling, cold chain, warehousing, and value-addition zones.

Strengthening Waterway Connectivity

Operationalization of NW-2 (Brahmaputra) and NW-16 (Barak) for cargo movement. The India-Bangladesh Protocol Route has opened direct international navigation for cargo, reducing transit time and cost. River ports at Pandu, Dhubri, Karimganj being modernised with container terminals.

Border Trade & International Linkages

Enhanced trade access with Bangladesh, Nepal, Bhutan & Myanmar. Proposed BBIN and BIMSTEC trade corridors will position Assam as a major transshipment centre. Land custom stations supported for export-import logistics.

Industrial & Warehousing Zones

Dedicated Logistics Parks, Warehousing Clusters and Cold Storage Networks near industrial estates. Support for Food Processing, Pharma, Tea, Bamboo, Textiles, Mining, Petroleum & FMCG logistics chains. Policy encourages Private-Public Partnerships (PPP) and 100% private investment participation.

Policy Incentives for Investors

Land subsidy, capital subsidy, power tariff incentives, and stamp duty exemptions for logistics companies. Incentives for cold chain, multimodal facilities, fleet development, and technology adoption. Special focus on Green Logistics, Renewable-powered warehouses, and e-vehicle freight movement.

Technology & Digital Integration

Promotion of smart logistics, digital freight management, GPS-enabled fleet tracking, and e-logistics platforms. Encouraging use of IoT, RFID, drone-based infrastructure monitoring, and warehouse automation. Why Assam is Emerging as a Logistics Powerhouse Strength Impact on Logistics Growth Strategic location connecting India to SE Asia Gateway for international trade. Road-Rail-Water-Air multimodal network reduces freight cost & delivery time. Upcoming MMLP & logistic parks attracts investment in storage & distribution access to border trade. Boosts export oriented industries Govt. support & incentives. Encourages private sector participation.

Opportunities for Business & Industry

- Cold chain for perishable goods (fruits, vegetables, meat, flowers)
- E-commerce fulfilment and last-mile distribution hubs, container freight stations and custom bonded warehouses.
- Hazardous & biomedical waste logistics (specialized segment)
- Tea export logistics, bamboo-value chain transport Fleet services, EV cargo mobility & logistics tech platforms.

Assam's logistics vision is centered on connectivity, capacity, and competitiveness. With multi- modal infrastructure, border trade access, digital integration, and investor-friendly incentives. The state is set to become an international logistics gateway for the Northeast & ASEAN markets. The Logistics Policy is not just a transportation reform-it is a blueprint to unlock industrial growth, export opportunities, and employment generation across the region.

मध्य भारत अंचल (ग्वालियर) में एलयूबी अभ्यास वर्ग संपन्न

प्रतिवेदन

सोबरन सिंह तोमर

अंचल अध्यक्ष

मध्य भारत, लघु उद्योग भारती

sobaransinghtomar@gmail.com

लघु उद्योग भारती, मध्य भारत अंचल द्वारा ग्वालियर में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग (13–14 दिसंबर, 2025) में अंचल के 15 जिलों के 120 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

उद्घाटन एवं वैचारिक अधिष्ठान:

- अ.भा. संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी ने 'दायित्व बोध' विषय पर कहा कि उद्यमी समाज का रक्षक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में उद्योग चलाने और संगठन को समय देने का आह्वान किया।
- अ.भा. उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल ने अभ्यास वर्ग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठनात्मक अनुशासन ही हमारी शक्ति है। वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से एक सूत्र में पिरोना है।

समूह-सह बैठक (औद्योगिक समस्याओं पर मंथन):

- इस विशेष सत्र में 15 जिलों के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को साझा किया। मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की ऊँची दरें, अघोषित कटौती और जर्जर बुनियादी ढांचे पर चिंता जताई गई। सरकार से एमएसएमई के लिए सरल नीतियों और त्वरित सहयोग की मांग पर एक श्वेत–पत्र तैयार करने का निर्णय लिया गया।

तकनीकी एवं नीतिगत सत्र:

- प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा ने 'फैसिलिटेशन काउंसिल' की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे उद्यमी अपने फंसे हुए भुगतान (Delayed Payment) को कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
- पूर्व अ.भा. अध्यक्ष श्री जितेन्द्र गुप्ता ने 'कार्यकर्ता' विषय पर प्रबोधन दिया। उन्होंने बताया कि संगठन का आधार समर्पित कार्यकर्ता होता है। एक आदर्श कार्यकर्ता को संगठन की कार्य पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है।
- श्री सुनील मिश्रा ने ZED सर्टिफिकेशन के महत्व को बताते हुए कहा कि शून्य दोष (Zero Defect) ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने का एकमात्र रास्ता है।
- प्रदेश संयुक्त महामंत्री श्री राजेश गर्ग ने 'उत्पाद समूह' (Product Group) की महत्ता बताई। उन्होंने समझाया कि समान उत्पाद वाले उद्यमी कैसे समूह बनाकर कच्चा माल सस्ता खरीद सकते हैं और अपनी मार्केटिंग शक्ति बढ़ा सकते हैं।
- श्री विनोद नायर ने 'कार्यकर्ता समन्वय' पर कहा कि संगठन में संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। एक–दूसरे के सुख–दुख में खड़ा होना ही सच्चे कार्यकर्ता की पहचान है।

14 दिसंबर, 2025 (तकनीकी नवाचार एवं संकल्प)

महिला कार्य एवं संगठन विस्तार :

- श्रीमती रश्मि गुर्जर ने महिला उद्यमियों को संगठन की मुख्यधारा में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवार और उद्योग के साथ–साथ सामाजिक उत्तरदायित्व में भी महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है।
- पूर्व अ.भा. अध्यक्ष श्री वज्जू भाई वगासिया ने संगठन विस्तार के व्यावहारिक अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे जमीनी स्तर पर छोटी–छोटी इकाइयाँ बनाकर हम एक विशाल औद्योगिक तंत्र खड़ा कर सकते हैं।

तकनीकी एवं आधुनिक सत्र:

- प्रदेश लीप प्रभारी श्री कपिल जयसिंघानी ने 'लीप पोर्टल' पर ऑनबोर्डिंग का जीवंत प्रदर्शन किया। उन्होंने समझाया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक छोटा उद्यमी भी सीधे वैश्विक ग्राहकों तक पहुँच सकता है।
- श्री कनिष्क श्रीवास्तव (भोपाल) ने 'How to Export' विषय पर निर्यात की सरल प्रक्रियाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि निर्यात केवल बड़े उद्योगों के लिए नहीं है, बल्कि लघु इकाइयां भी गुणवत्ता के दम पर विदेशों में अपनी धाक जमा सकती हैं।
- श्री महेश करनोदिया ने 'Energy Saving' के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने जानकारी दी कि कैसे छोटे–छोटे तकनीकी सुधारों से बिजली के बिल में 20% तक की कमी लाई जा सकती है।

समापन सत्र:

- प्रदेश महामंत्री श्री अरुण सोनी ने डाटा संग्रहण और प्रेस–विज्ञप्ति की तकनीक पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने संगठन विस्तार के लिए नवीन प्रयोगों से प्रभावी कार्य करने के सूत्र दिए।
- श्री ताराचंद गोयल ने अभ्यास वर्ग के महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए आगामी कार्ययोजना के संकल्प दिलाए।
- आ. श्री प्रकाश चंद्र जी ने संगठन के आगामी कार्य विस्तार हेतु कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने कहा– "संगठन की शक्ति संख्या में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के सक्रिय और जीवंत संपर्क में निहित है; हमें हर तहसील तक लघु उद्योग भारती की वैचारिक ध्वजा पहुँचानी है। आगामी समय में हमारा लक्ष्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक उद्यमी को राष्ट्र–निर्माण की इकाई बनाना है, ताकि 'स्वावलंबी भारत' का स्वप्न साकार हो सके। कार्यकर्ता संगठन का वह प्राण–तत्व है जो अपनी निस्वार्थ सेवा से औद्योगिक समस्याओं और सरकारी तंत्र के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। ग्वालियर का यह अभ्यास वर्ग हमारे लिए विश्राम नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष और विस्तार का आरंभ है; यहाँ से ली गई ऊर्जा को हमें अपने–अपने जिलों में कार्य–रूप में परिणत करना है।"

❑❑❑

Special Report on the 'Pali Model' of Skill Development Presented to CM Rajasthan

A special report, based on various skill development projects operating in Pali- Rajasthan's largest textile processing hub, was presented to Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma by Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor of Udyog Times on 18th December at CM Residance. This initiative was undertaken by Laghu Udyog Bharati.

Dr. Mishra explained that after the global COVID-19 pandemic, inspired by the Rashtriya Swayamsevak Sangh and under the able guidance of Shri Prakash Chandra ji, National Organizing Secretary of Laghu Udyog Bharati, the local Pali team connected a large number of women with skills such as Tailoring, Bangle making, Mehandi-Beauty Parlour and pottery, and provided them with free training and employment opportunities. This skill development program has become renowned nationwide as the 'Pali Model'.

Dr. Mishra also urged that the B.Voc. (Bachelor of Vocation) program be recognized as equivalent to a graduate degree, in line with the mandate of the UGC, New Delhi and the practice in Haryana State, so that skilled employees can be made available to the MSME sector.

On this occasion, Dr. Mishra extended his heartfelt wishes to Chief Minister Shri Sharma on the second successful anniversary of the Rajasthan Govt. under his dynamic leadership and discussed skill development and vocational education in the state.

एलयूबी महाकौशल प्रांतीय अभ्यास वर्ग एवं उद्यमी सम्मेलन

प्रतिवेदन
अनिल वासवानी
अध्यक्ष, महाकौशल अंचल
लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश
dikatnimp@yahoo.co.in

लघु उद्योग भारती मध्यप्रदेश के महाकौशल अंचल के दो दिवसीय अभ्यास वर्ग एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन 20–21 दिसंबर, 2025 को मंगलायतन विश्वविद्यालय परिसर, जबलपुर में किया गया।

उद्घाटन सत्र– कार्यक्रम का शुभारंभ अ.भा. उपाध्यक्ष श्री ताराचंद गोयल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह श्री उत्तम बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अंचल अध्यक्ष ने स्वागत उद्बोधन में सभी सत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं के परिचय–सत्र के साथ ही अंचल की विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित हुआ।

संगठन सत्र– प्रदेश महामंत्री श्री अरुण सोनी ने डेटा संग्रहण, प्रेस विज्ञप्ति और संगठन विस्तार के नवीन प्रयोगों पर मार्गदर्शन दिया। वहीं श्री ताराचंद गोयल ने अभ्यास वर्ग के महत्व पर प्रकाश डाला।

तकनीकी एवं डिजिटल सत्र– श्री सौरभ तोमर ने 'लीप पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग और श्री कनिष्क वास्तव ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए निर्यात (Export) की बारीकियों को समझाया।

गुणवत्ता एवं ऊर्जा सत्र– श्री अखिलेश मेहरा ने ZED सर्टिफिकेशन और श्री महेश करनोदिया ने उद्योगों में Energy Saving (ऊर्जा बचत) के उपायों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

पाथेय सत्र– प्रांत कार्यवाह श्री उत्तम बनर्जी ने 'कार्यकर्ता एवं दायित्व बोध' विषय पर राष्ट्र निर्माण में लघु उद्योगों की भूमिका को रेखांकित किया।

शासकीय नीतियां सत्र– क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर श्री राकेश सहरावत ने EPFO की नई प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा ने एमएसएमई काउंसिल और औद्योगिक नीतियों पर मार्गदर्शन दिया।

महिला-कार्य सत्र– अंचल महिला कार्य प्रभारी श्रीमती प्रियंका सोनी ने महिला उद्यमियों की भूमिका और संगठन में उनकी बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की।

प्रबंधन एवं समापन सत्र– श्री बिंद्रेश नेमा ने कार्यकर्ता समन्वय और श्री मनीष सिंह ने बिजनेस व टाइम मैनेजमेंट पर प्रभावशाली जानकारी साझा की। मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीम ने PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से सहयोग के नए आयाम प्रस्तुत किए। श्री ताराचंद गोयल ने आगामी वर्ष हेतु सदस्यता लक्ष्य और इकाइयों की सक्रियता पर समापन उद्बोधन दिया। यह दो दिवसीय अभ्यास वर्ग अनुशासन, ज्ञान और उत्साह का संगम रहा। इस आयोजन ने महाकौशल अंचल के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया, जो निश्चित ही संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर– संगठन में पहली बार कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सम्मेलन स्थल पर ही निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया गया। आधुनिक 'मोबाइल हेल्थ वैन' के साथ डॉक्टरों की टीम ने सभी पदाधिकारियों और उद्यमियों का पूर्ण शरीर परीक्षण किया।

ऐतिहासिक MOU– लघु उद्योग भारती और मंगलायतन विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे छात्रों को उद्योगों में प्लेसमेंट और उद्यमियों को शैक्षणिक सहयोग प्राप्त होगा।

LUB's Delegation Invited Dignitaries for India StoneMart- 2026

Countdown Starts for International Exhibition @ Jaipur

Lok Sabha Speaker Shri Om Birla

Union Minister for External Affairs Shri S. Jaishankar

Union Minister for Railways Shri Ashwini Vaishnaw

Union Minister for Tourism and Culture
Shri Gajendra Singh Shekhawat

Union Minister of Law and Justice
Shri Arjun Ram Meghwal

Union Minister for Environment, Forest and
Climate Change Shri Bhupender Yadav

LUB's Delegation led by National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra ji invited dignitaries to "India StoneMart - 2026" which will be held at Jaipur on 5-8 February. On this occasion, National Jt. GS Shri Rakesh Garg & Shri Naresh Pareek, and Convener Shri Natwar Lal Ajmera were also present on 9th Dec. 2025.at New Delhi.

Dy. Chief Minister Rajasthan Smt. Diya Kumari unveiled the official poster of India Stone Mart-2026 in the presence of Team LUB- National Jt. GS Shri Naresh Pareek, Convener Shri Natwar Lal Ajmera, State Treasurer Shri Arun Jajodia, Jaipur Anchal President Shri Mahendra Mishra and others.

LUB's Makrana and Kishangarh Units conducted a meeting with marble traders on 28th Dec. to discuss the India StoneMart-2026, the challenges facing the marble industry, and concrete strategies to connect the marble trade with new opportunities. On this occasion; LUB's National Jt. GS Shri Naresh Pareek, India StoneMart Convenor Shri Natwar Ajmera, Shri Deepak Ajmera, Shri Mukul Rastogi, Shri Sanjeev Modi, former MLA Shri Shriram Bhinchar, BJP District President Smt. Sunita Rander, Marble Association President Shri Sudhir Jain, and LUB unit President Shri Umesh Goyal were present.

With the objective of strengthening the efficiency and competitiveness of MSMEs, LUB's Dewas unit organized a significant workshop under the RAMP scheme. Practical information was provided on the MP MSME Development Policy - 2025, MP MSME Land Rules, MP Startup Policy, Lean/IPR/ZED schemes, and the New Labour Law Codes.

नए श्रम संहिताओं (New Labour Codes) का विवरण

भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर इन्हें **4 Labour Codes** के रूप में 21 नवंबर, 2025 से पूरे देश में लागू किया।

वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages):

- पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन (National Minimum Wage) का प्रावधान।
- हर कर्मचारी को समय पर वेतन देना अनिवार्य।
- निजी और सरकारी–दोनों सेक्टरों पर लागू।
- "Wages" की परिभाषा एक समान–Basic + DA = वेतन का 50% से कम नहीं हो सकता।
- ओवरटाइम वेतन दोगुना मिलेगा।
- Equal pay for equal work – लिंग, जाति, धर्म पर भेदभाव नहीं।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code):

- 300 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में छंटनी / बंद के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक।
- कम संसद / यूनियन विवादों के लिए Industrial Tribunal की व्यवस्था।
- हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य।
- कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संवाद बढ़ाने के लिए Works Committee।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code):

- PF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, पेंशन–सबको एक कानून में लाया गया।
- Gig workers (Zomato, Ola, Uber) और Platform workers को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ।
- Fixed term employees को 1 साल में ग्रेच्युटी पात्रता।
- Construction मजदूर, असंगठित मजदूर – सबके लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ।
- कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) विस्तार।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-स्थिति संहिता (OSHWC Code):

- एक लाइसेंस– एक रजिस्ट्रेशन– एक रिटर्न (Single Registration System)।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक सख्त।
- महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था के साथ।
- 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का फ्री हेल्थ चेकअप।
- मजदूरों के लिए साफ पानी, रोशनी, वेंटिलेशन, शौचालय, सुरक्षा गियर अनिवार्य।
- Contract workers की सुरक्षा बढ़ाई गई।
- कार्य समय (Working Hours) – सभी को प्रभावित करने वाला बड़ा बदलाव
- रोजाना 8 से 12 घंटे काम करने की अनुमति, लेकिन साप्ताहिक काम 48 घंटे से अधिक नहीं।
- ओवरटाइम का भुगतान Double (2x)

मजदूरों को क्या फायदा?

- समय पर वेतन
- बेहतर सुरक्षा और हेल्थ सुविधाएँ
- एक साल में ग्रेच्युटी (Fix-Term Employees)
- रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा
- PF/ESI सभी तक व्यापक रूप से पहुँचेगा
- Gig workers को भी Social Security

नियोक्ता(Employers)के लिए क्या बदलाव?

- कम कागज़ी काम – Single License] Single Return
- निरीक्षण (Inspection) में "Facilitator Approach"
- कर्मचारियों को Appointment Letter देना अनिवार्य
- कामगारों की सुरक्षा के नियम कड़े

आलोचना- कुछ यूनियनें कहती हैं–कामगारों की छंटनी आसान होगी। अधिक घंटों के कार्य–दिवस पर सवाल। ये राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे कितने प्रभावी ढंग से इन्हें लागू कर पाती हैं।

❑❑❑

LUB's NEWS in Brief

Under the Industry-Academia Connect Program; LUB's Karnataka State Unit has signed an MoU with the D-CoE, Department of Design & Manufacturing (formerly CPDM), IISc Bangalore, to support MSMEs in Industry 4.0 and other critical technologies on 11th Dec. 2025.

The DRPSC (Department-Related Parliamentary Standing Committee) on Industry led by MP Rajya Sabha & Chairperson Shri Tiruchi Siva and 20-member delegation visited Amritsar to review the performance of PMEGP (Prime Minister Employment Generation Program) in the Punjab on 30th Dec. 2025. The LUB was also invited for this meeting and represented by National VP Adv. Arvind Dhumal & Gen. Secretary-Punjab Shri Vivek Rathour.

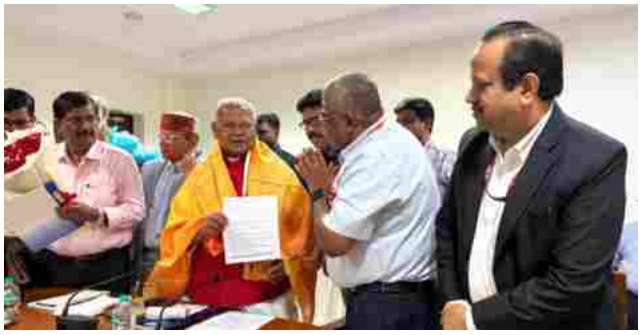

LUB's Tamil Nadu State team led by National EC Member Shri Hariharan and State Jt. GS Shri Jayendran met Union MSME Minister Shri Jitan Ram Manjhi and handed over memoranda of requests concerning MSMEs, in Tamil Nadu at Chennai on 29th Dec. The Minister assured for grievances would be looked into.

RSS Sahsarkaryawah Dr. Krishna Gopal ji visited Sohan Singh Memorial Skill Development Centre, run by Laghu Udyog Bharti at Jaipur on 2nd Dec. On this occasion, LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandraji, National Jt. GS Shri Naresh Pareek, RSS Prant Pracharak Shri Babulal Sharma and skill center co-ordinator Shri Mahendra Khurana were present.

A delegation led by Shri Om Prakash Gupta, National General Secretary of LUB, met with Shri Ajit Chavan, Additional CEO-GeM, and highlighted various problems faced by members on the GeM portal. Delhi State President Shri Diwan Chand Gupta, General Secretary Smt. Aarti Sehgal and GeM Convener Shri Janak Bhatia were also present.

LUB's Kerala Team submitted the Study Report on PMEGP Scheme to the Parliamentary Standing Committee Chairman at Kochi on 27th Dec. 2025.

LUB's National Magazine Udyog Times dedicated November Edition to NRRs (Non-Resident Rajasthanis) was launched by Dy. Chief Minister & Tourism Minister Smt. Diya Kumari and Dy. Chief Minister & Higher Education Minister Dr. Premchand Bairwa at Jaipur on Pravasi Rajasthani Divas organised by Govt. of Raj on 10th Dec.Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor-Udyog Times, introduced the office bearers of various chapters. Former National Treasurer CA Yogesh Gautam and Jaipur Anchal President Shri Mahendra Mishra welcomed the various chapter presidents of the Rajasthan Foundation. On the occasion, Former National President Shri Ghanshyam Ojha, National Jt. GS Shri Naresh Pareek, State Treasurer Shri Arun Jajodia, and Vice President Shri Natwarlal Ajmera were also present.

LUB's Chhattisgarh State Team met Additional Commissioner, MSME GoI Smt. Ashwini Lal to discuss about upcoming Trade Fair.

LUB-Karnataka Team had a very comprehensive discussion with Smt. Kavitha Gowda, Ministry of MSME on 29th Dec. During the meeting, a copy of the proposal for establishing a Material Testing Laboratory, earlier submitted to the Minister for MSME, was presented to her for consideration. In addition, the Team presented various ongoing and proposed initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem.

LUB's Tamilnadu State Working Committee Meeting presided by State President Shri Chezian was conducted in presence of National Jt. General Secretary Shri Mohanasundaram and VP Shri Vijaya Ragavan at State Head office, Chennai on 21st Dec. 2025.

LUB's Delegation met Director General, Bureau of Indian Standards Shri Sanjay Garg to address key quality standards challenges confronting small enterprises. Discussions focused on aligning regulatory norms with practical industry realities and fostering collaborative implementation strategies. Deliberations highlighted the need for developing testing labs, supporting grassroots economic growth, and framing flexible standards that empower-rather than constrain-small manufacturers. Representatives underscored the value of understanding on-ground challenges through consultation, handholding, and adaptive frameworks to strengthen India's MSME ecosystem.

RM UPSIDA Shri Anil Sharma handed over Allotment Letter of Laghu Udhyog Bharti Office at Site-B, CFC Building, Surajpur, Greater Noida to Shri Sanjay Batra, General Secretary, District GB Nagar & Shri Satish Singh, Secretary UPSIDA Chapter, Greater Noida.

The poster for Swayamsidhha Premium Lifestyle Exhibition, organized by LUB's Kota Women's Wing, was unveiled on by Lok Sabha Speaker Shri Om Birla on 22nd Dec. On the occasion, National Advisor Shri Govindram Mittal, State Executive Member Shri Achal Poddar, Kota unit President Smt. Chandni Poddar, along with executive members Smt.

Ritu Goyal, Smt. Sangeeta Mittal, Smt. Komal Khandelwal, and Smt. Manju Bansal were present.

LUB's Trichy Women Team conducted a meeting to discuss opportunities available for women entrepreneurs and the industrial opportunities under CSIR for starting new ventures. A significant highlight of the day was the formation of the Trichy Mahila Team. Shri Sathyanarayanan, State EC Member from Coimbatore and Shri Jeyandran provided excellent guidance.

LUB's Women Wing Ajmer organized an Industrial Visit for students of Dayanand College to Goyal Proteins Ltd. Kota. The students received valuable guidance related to decision-making process, safety standards, supply chain management, and quality control.

Opportunities for Technology Transfer

Laghu Udyog Bharati (LUB) is pleased to share a sector-wise portfolio of technologies from VIT Vellore available for technology transfer and commercialization. Members are encouraged to identify technologies that can improve manufacturing processes, enhance product quality, or enable new product development.

Technology Sectors Covered:

- Agri and Food Processing
- Automobile and Transportation
- Biotechnology and Pharmaceuticals
- Chemical Engineering
- Clean and Green Energy
- Computer Science and IT
- Electrical and Electronics
- Material Science
- Mechanical and Industrial Engineering.

For clarifications, please contact: Dr. Arshpreet Kaur, Nodal Officer- Research & Industry Collaborations, LUB Cell: 9915906676.

industryacademia.lub@gmail.com

LUB's Coimbatore Unit (TN) organized an Awareness Program on Business Development on 5th Dec. Keynote Speaker Shri Jeyendran Jt. Gen. Secretary gave insight into how to plan with SWOT Analysis, moving forward accurately with the LEAP Framework.

Many participants self realized errors at their existing business operations, realization, and corrective measures to be taken for growth.

Shri Kalyanasundaram General Secretary spoke about importance of LEAP portal and urged to register their products on the portal and make their business presence Pan India. Shri Sivasathi - District president welcomed the gathering and Shri Jayakanthan - Distt. Secretary submitted activity report for the month State VP Shri Ravichandran, Shri Nallathami and Masscomm member Shri Sathyanarayanan participated in the event. Shri Vathiraja Distt. Treasurer gave vote of thanks.

LUB's Valsad District Unit (Gujarat) conducted a meeting at GIDC, Vapi to discuss upcoming programs on 22nd December.

Under the guidance of Haryana State Treasurer Shri Raman Chawla and Meerut Sambhag President Shri Pawan Singhal, **the monthly meeting of GB Nagar district was held in the presence of GST Joint Commissioner Shri K.K. Rai on upcoming programs** on 19th December. The important issues including membership directory, the new office, and the problems faced by new members were discussed. Shri Rai stated that no vehicle would be seized for minor clerical errors. He also clarified that no audit or notice can be issued to any GST-registered vehicle that is less than seven years old. GB Nagar President Shri Naresh Gupta, General Secretary Shri Sanjay Batra, and Treasurer Shri Dinesh Chandak, along with other active members, were present at the meeting.

An important meeting of LUB's Udaipur Unit was held on 17th Dec. with the special presence of National General Secretary Shri Om Prakash Gupta. Shri Gupta called upon all responsible members to actively participate in strengthening, making the organization more effective, and achieving tangible results through the following 3 key points:

1. **Social Media Empowerment-** To enhance LUB's digital presence, all members should encourage their family members and colleagues to follow the official Facebook, X, and Instagram pages.
2. **LEAP Portal Registration as a Top Priority-** Registration of all members on the LEAP portal and the creation of a Seller-Buyer network. The goal is to have over 1 Lakh certified members to continuously increase business, opportunities, and collaboration through this portal.
3. **One Member-One Project-One Year-**Every responsible member should take on a concrete project and complete it within a year, presenting the results to the organization. Projects could include-
   - RIICO land/industry records
   - Providing benefits of Startup schemes to existing industries
   - Effective implementation of MSME schemes • Solving local industrial problems.

On this occasion, Smt. Jayanti Goyla (National Coordinator - Net Zero & Industry-Academia Initiatives) and Dr. Arshpreet Kaur (Nodal Officer, Research & Industry Collaborations) were introduced.

Kerala- State-Level Interaction Meeting at Thrissur

LUB's Kerala State Unit conducted an Interactive Meeting on 27th Nov. at MSME-DFS, Thrissur. State President Shri Suresh Kumar welcomed the gathering. Shri Prakash GS, IEDS- Joint Director, MSME-DFS, appreciated LUB's initiatives and assured full support for joint programs, scheme awareness, helpdesk services, and quick coordination with senior officials. State GS Shri Babu Ayyenchera reviewed the last two years' progress and future plans. Shri Vinod Kumar National EC Member shared inputs for organisational strengthening.

Shri. Mohansundaram, National Jt. GS, stressed on organisation building, strong core teams, disciplined Members. Shri M.S. Vijayaragavam, National VP highlighted MSME development opportunities and membership expansion. Shri. M. Sivakumar, National Executive Member & State Coordinator emphasised on Zone-wise programs with SIDBI support, Training for Zonal Karyakartas at MSME-DI Thrissur, Helpdesks in all districts, CSIR-supported women entrepreneurship programs, LEAP initiatives, State-level MSME Expos and Grievance Committee.

Tamil Nadu State GS Shri. Kalyan Sundaram and State VP Shri S. Ravichandran were present also as special invitees.

LUB's Rewa Women's Unit of Mahakaushal Anchal (MP) was formed with Parivar Milan on 7th December. Smt. Namrata Verma was announced as the District President and Smt. Amrita Kesharwani as the District Secretary, along with 8 other women office bearers. On this occasion, RSS District Sanghchalak Dr. S. N. Tiwari, Prant Sampark Pramukh Shri Harish Chandra Dwivedi, Vibhag Pracharak Shri Hari Narayan, LUB's State GS Shri Arun Soni, DIC GM Shri Tiwari, Mahakaushal Women's Work In-charge Smt. Priya Soni, Vice President Shri Ramchandra Agrawal and Joint Secretary Shri Updesh Pansari, District President Shri Deepak Madan, and Sambhag Executive Member Shri Rahul Dwivedi were present. District Secretary Shri Santosh Dubey expressed Vote of Thanks.

LUB's Bikaner unit has Trained 32 Skilled Female Beauticians

A 40-day training program for Beautician was conducted in collaboration with Laghu Udyog Bharti Bikaner, Jan Shikshan Sansthan, and the North Indian Railway Women's Welfare Organization, has concluded. 32 women received training during this program. Smt. Rakhi Chordiya, President Women's Wing told that Dr. Ashu Malik and Smt. Deepti Govil, wife of the Bikaner DRM, actively contributed to the success of this training program.

LUB's Visakhapatnam Unit and GITAM (Deemed to be University), signed an MoU to deepen Industry-Academia collaboration and accelerate innovation for the MSME sector on 2nd Dec. The hybrid event opened with an address by Prof. Gouthama Rao, Pro Vice-Chancellor, GITAM, followed by an overview of GITAM's innovation ecosystem by Prof. Raja P. Pappu, Dean, GITAM School of Business and Coordinator, DST G-TEC Project. Smt. Jayanti Goela, National Coordinator - Industry Academia outlined LUB's national initiatives to connect Industry and Academia. Insights were also shared by Shri Om Prakash Gupta, National General Secretary-LUB, Dr. Krishna Kanth Pulicherla, Scientist, DST, New Delhi; Dr. D. Gunasekaran, Registrar, GITAM; Shri T. Yogish Chandra, President, LUB Andhra Pradesh; Shri A. Krishna Balaji, AIWC Member, LUB and Shri Amit Goyal, National Coordinator - Technology Transfer, LUB

This collaboration is an important milestone in connecting GITAM's research strengths with LUB's MSME network to drive practical, solution-oriented innovation.

On the 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji, a recitation of Sukhmani Sahib was organized jointly by LUB's Women's Wing Jalandhar (Punjab), and the Saraswati Sindhu Trust. State VP Smt. Seema Dhumal highlighted the life and unparalleled sacrifice of Guru Tegh Bahadur Ji. Women's Wing Punjab Convener Amardeep Shergill, Co-Convener Smt. Mona Mongia-Dera Bassi, Smt. Aarti Sachdeva President- Jalandhar unit, Smt. Raman Preet Kaur General Secretary, Smt. Saroj Thakur, and other women entrepreneurs were present.

LUB's Belgavi Women cell & Rani Chennamma University and Pandit Deen Dayal Upadhyaya Peeth organized special Session on Skill Entrepreneurship Awareness at Bhartesh College. Shri Satyanarayan Rao Joint Director-DIC, Smt. Priya Puranik-LUB and Dr. Navi-Rani Chennamma University spoke on Schemes, qualities, and Startups.

LUB's Krishnagiri Unit of Tamilnadu State conducted Installation Ceremony for new team at Hosur on 5th Nov. Under the guidance of National VP Shri Vijayaraghavan, the new district team for the term 2025-2027 was formally announced. President Shri Sivakumar and General Secretary Shri Karupaiah, along with 12 office bearers, took their oath. During the event, a special program on the Importance of Intellectual Property Rights, Trademarks, and Patents was jointly organized by TNCST and IPFC.

LUB's Bhilwara Unit of Rajasthan State and Swaniti Initiative jointly organized a seminar on Energy and Modern Technology in Industries on 16th December. The seminar focused on modern and cost-effective technologies, government schemes for energy saving, energy subsidies and financing schemes, and information on green energy. Senior Strategic Advisor Dr. Bhaskar Natarajan and his team gave a presentation on the need for and preparation for future energy saving, explaining that excellent results in energy conservation can be achieved through energy resource audits, efficient equipment, technology upgrades, and environmental compliance. District Collector Shri Jasmeet Singh Sandhu stated that the state government is always ready to cooperate in the green energy sector. LUB's National General Secretary Shri Om Prakash Gupta, encouraged all the members present to increase the number of industrial members in proportion to the population and to provide greater support to industries by coordinating fully with various departments. Chittorgarh Anchal President Shri Mahesh Hurkat emphasized the crucial importance of affordable energy and technology for industries. Smt. Jayanti Goyla shared her views on net-zero emissions.

Representatives from institutions such as the DIC, RIICO, Ajmer Vidyut Vitran Nigam, State Employees' Insurance, Pollution Control Board, and SIDBI were present at the seminar, along with industrialists Shri Rameshwar Lal Kabra, convener Shri Om Prakash Jagetiya, and entrepreneurs from Kishangarh, Asind, Bijolia, and Gangapur. The program was conducted by Shri Sumit Jagetiya and Smt. Kavita Jagetiya. Earlier, National General Secretary Shri Om Prakash Gupta visited the industrial complex of Manomay Tex India Ltd. and shared organizational principles with the Bhilwara unit members.

A "Intellectual Property Rights (IPR) Awareness Program" was organized under the joint auspices of Laghu Udyog Bharti, Dewas (Madhya Pradesh) and the MSME Department of the Govt. of India, Indore at Prestige Institute of Management, Dewas. The program featured experts who shed light on the overview and types of IPR (Patent, Trademark, Copyright) and case studies, the role of IPR in business strategies for MSMEs and startups, and the financial and policy schemes of the Government of India for MSMEs and startups.

A three-day skill development program on "Mushroom Cultivation and Value Addition for Livelihood Generation in Arid Regions" was successfully conducted under the joint auspices of Laghu Udyog Bharti, Jodhpur Prant, and the Central Arid Zone Research Institute (CAZRI). The camp was held at the Agribusiness Incubation Centre on the CAZRI campus in Jodhpur. CAZRI Director, Dr. Surendra Pal Singh Tanwar, provided detailed information about new research-based technologies, research findings, and innovations. He stated that mushroom production has become a highly profitable business for women in arid regions, offering high returns with low costs and minimal investment. Program coordinator, Smt. Manju Saraswat, said that such training camps will empower women and help them become self-reliant. LUB's Jodhpur Prant VP Shri Harish Lohia & GS Shri Suresh Vishnoi were also present.

A 31-day sewing training program, conducted at the Saksham Bharat Skill Development Center under the joint auspices of LUB's Alwar unit and Alwar Chamber of Industries, in collaboration with PNB Rural Self-Employment Training Institute and RSETI, has concluded. The main objective of this training program was to empower women by equipping them with the skills necessary for self-employment and making them self-reliant. Participants were provided with practical knowledge of modern sewing techniques.

LUB's Alwar Unit will assist trained women in securing project-based work, including orders for industrial uniforms, school uniforms, and corporate/institutional orders. Additionally, interested women will receive comprehensive support in setting up boutiques/self-employment units, including necessary guidance, market linkages, and enterprise management.

LUB's UP State Unit & International Zinc Association jointly organized a seminar, which was inaugurated by the State Joint General Secretary, Shri Gaurav Mittal. Ryan Winter, a zinc expert from IZA-USA, provided important information related to zinc products.

LUB's Lakshmibai Women's Unit organized the Swayamsiddha exhibition at Udaipur on 1-3 November in which 101 exhibitors from various parts

of the country, including Punjab, Gujarat, Hyderabad, Kishangarh, Chittorgarh, and Bhilwara, showcased their quality products. Purchases worth approximately ₹55 lakh were made at the exhibition. All visitors received CPR training, which was a useful and beneficial aspect of the event. Twenty social groups were invited and honored each day, widely disseminating the message of women's empowerment and participation in society. The main sponsor was PMCH, and the co-sponsors were Rajendra Toyota, Geetanjali Medical College & Hospital, and Laureate High School. One2All and MyFM made a special contribution as social media partners.

LUB's Madurai Unit of Tamil Nadu state witnessed the installation ceremony of its new team led by Shri Shyam as President and Shri Jagapathi Raju as General Secretary on 15th Nov. National Jt. GS Shri Mohanasundaram, VP Shri Vijayaraghavan, TN General Secretary Shri Kalyansundaram, Jt. GS Shri Jayendran & VP Shri Aravind guided the new team. MSME Zone Director Shri Saravanan was also present. A significant milestone of the ceremony was the signing of an MOU with VIT Engineering College, Vellore, facilitated through the efforts of Shri Senthil & Shri Jayendran.

LUB's Bareilly unit conducted an industrial visit to BL Agro Industries and the members gained new insights into agro-processing.

❑❑❑

राजस्थान सरकार

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

- किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत **76.18 लाख** किसानों को **₹10,432 करोड़** से अधिक की राशि हस्तान्तरित

- **राइजिंग राजस्थान ग्लोबल** इन्वेस्टमेंट समिट में **₹35 लाख करोड़** के एमओयू
- **₹8 लाख करोड़** के निवेश के कार्य प्रारंभ

- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में **1.36 लाख** एवं शहरी में **68,738 आवास** कार्य पूर्ण

- **17 जिलों** में राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी) के लिए **₹26 हजार करोड़** के कार्यादेश जारी

- **3.96 लाख** पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड
- **5 लाख** दुग्ध उत्पादकों को **₹1,172 करोड़** की सहायता

- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में **35 लाख रोगियों को ₹6,860 करोड़** से अधिक का कैशलेस उपचार

- **92 हजार पदों** पर नियुक्तियां, **1.53 लाख** पदों पर नई भर्तियां

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत **₹6,207 करोड़** के बीमा क्लेम वितरित
- पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-बी के तहत **53,571 सोलर** पम्प सेट की स्थापित

- **16,430 किमी.** नई सड़कें बनी, **प्रतिदिन 23** किमी. सड़क का निर्माण

- **1,754 खिलाड़ियों** को **₹39.57 करोड़** सहायता
- **658 स्टार्टअप्स** को **₹22.48 करोड़** की सहायता

- महिला सुरक्षा के लिए **500 कालिका** पेट्रोलिंग यूनिट का गठन
- महिला अपराधों में **12 प्रतिशत** की कमी

- ऊर्जा उत्पादन को **28 प्रतिशत (6,839 मेगावाट)** बढ़ाया
- **428.18 मेगावाट क्षमता के 1.05 लाख** रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित

- **13.89 लाख** स्वामित्व कार्ड जारी
- कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में **₹26 प्रतिदिन की वृद्धि**

- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान और एक पेड़ माँ के नाम के तहत **19 करोड़ वृक्षारोपण**

- मेधावी विद्यार्थियों को **88,724 टैबलेट** वितरित
- छात्राओं को **10.51 लाख साइकिलें** एवं **39,664 स्कूटियां** वितरित

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में चहुंमुखी विकास के लिए **6,019 ग्राम चयनित**

- गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस सिलेण्डर **₹450** में उपलब्ध
- लाडो प्रोत्साहन योजना में **₹1.50 लाख** सेवा बॉण्ड से **4.60 लाख बालिकाओं को लाभ**

नव उत्थान - नई पहचान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान पत्रिका

UDYOG TIMES

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 December-2025
Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

सत्यमेव जयते
Government of Rajasthan

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
India

Shri Bhajanlal Sharma
Hon'ble Chief Minister
Rajasthan

Shri Rajyavardhan Rathore
Hon'ble Minister for
Industry and Commerce
Rajasthan

Shri K.K. Vishnoi
Hon'ble Minister of State for
Industry and Commerce
Rajasthan

INDIA'S BIGGEST
STONE INDUSTRY SHOWCASE

13th
INDIA STONEMART2026
Stone for Sustainability
5 - 8 February, 2026
JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

REGISTER NOW
stonemart-india.in

Organiser
CDOS
Centre for Development of Stones

Principal Sponsor
RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

Co-Organiser
LAGHU UDYOG BHARATI

Fair Sponsor
RK MARBLE
KHOOBSURAT MAANDAARI

info@stonemart-india.in | www.stonemart-india.in | +91-7300053633

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019